राजगढ़ तहसील क्षेत्र में गत 16 जुलाई से चल रहा किसानों का चक्का जाम आंदोलन सोमवार को किसानों और कलैक्टर के बीच हुई वार्ता के बाद खुल गया।

58 घंटों बाद खुला राजगढ़ में किसानों का चक्का जाम

चूरू जिला कलैक्टर के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता सफल रही और किसानों ने जमकर आतिशबाजी की

- **प्रशासन द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट नहीं देने के विरोध में और बकाया बीमा क्लेम सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 जुलाई से राजगढ़ तहसील क्षेत्र में किसानों का चक्का जाम आंदोलन चल रहा था।**
- **राजगढ़ तहसील के अलावा डोकवा, लसेड़ी, ददरेवा, सिद्धमुख व बैरासर में भी किसानों ने चक्का जाम कर रखा था, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लम्बी कतारें लग गई थीं।**
- **चक्का जाम खुलने के बाद वाहन चालकों सहित स्थानीय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है।**

सादुलपुर, 18 जुलाई (निसं)। अखिल भारतीय किसान सभा एवं भारत की जनवादी नौजवान सभा को प्रशासन द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट नहीं देने के विरोध में एवं नहर व बकाया बीमा क्लेम सहित 18 सूत्री माँगों को लेकर तहसील क्षेत्र राजगढ में चल रहा, चक्का जाम प्रदर्शन तीसरे दिन जिला कलेक्टर चूरू के साथ सकारात्मक वार्ता होने के बाद स्थगित हो गया है।

ज्ञातव्य है कि राजगढ तहसील के एन.एच. 52 पर स्थित गाँव डोकवा, सादुलपुर हिसार एन.एच. 52 पर स्थित लसेड़ी, तारानगर सादुलपुर सड़क मार्ग पर धोलिया (ददरेवा), सिद्धमुख भादरा सड़क मार्ग पर सिद्धमुख में एवं सादुलपुर झुन्झुनूं सड़क मार्ग पर गाँव बैरासर छोटा में गत तीन दिन व दो रात से लगभग 58 घंटे से चक्का जाम चल रहा था।

पाँच सूत्री मांगों का समझौता पत्र सौंपने के बाद सोमवार शाम 6.00 बजे रास्ता खोल दिया गया। इसी दौरान किसानों ने जमकर आतिशबाजी भी की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक पेमाराम, डॉ. संजय माधव, अध्यक्ष रामनिवास लाम्बा, कॉमरेड सुनील पूनिया, निर्मल कुमार प्रजापत, उमराव सिंह, मुनेश पूनिया, इन्द्राज सिंह आदि के नेतृत्व में, चूरू जिला कलैक्टर सिद्धार्थ सिहाग के साथ चूरु, जिला कलैक्टर कार्यालय चूरू में वार्ता हुई, जिसमें किसानों की मांगों को मान लिया गया तथा वार्ता सफल होने के बाद सभी जगहों से चक्का जाम खोल दिया गया।

आंदोलन कर रहे किसानों ने इसे अपनी जीत बताया और जमकर नारेबाजी की। हांलाकि रविवार मध्यरात्रि को जिला कलैकटर चूरू, सिद्धार्थ सिहाग एवं एसपी चूरू, दिगंत आनन्द किसानों से वार्ता करने के लिए तारानगर आये थे, मगर वार्ता असफल रही थी।

चक्का जाम खुलने पर चूरू से लेकर डोकवा तक लगी वाहनों की लम्बी-लम्बी कतारों में खड़े वाहन चालकों एवं लगभग एक सप्ताह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जूझ रहे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।

गौरतलब है कि लिखित समझौता वार्ता के अनुसार जिला प्रशासन क्रॉप कटिंग खरीफ 2021 की रिपोर्ट 22 जुलाई तक उपलब्ध करवाएगा। जिन किसानों को पूर्व में क्लेम भुगतान बैंकों की त्रुटियों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उनको राज्य सरकार द्वारा, पत्र 05 अप्रेल 2022 के माध्यम से अभिशंषा करते हुए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं। कहा गया है कि, शीघ्र क्रियान्वयन के प्रयास किये जायेंगे, प्रीमियम न काटे जाने तथा पोर्टल पर इन्द्राज न करने के कारण लम्बित क्लेम के लिए संबंधित बैंक का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा।

राज्य सरकार की कृषि योजनाओं में पूर्व स्वीकृति की तुलना में इस वर्ष अधिक स्वीकृतियां जारी की जायेंगी और यदि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर 181 पटवार हल्कों के संबन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, जिसमें क्लेम का निर्धारण केवल क्रॉप कटिंग के आधार पर करने का निवेदन किया जाता है, तो उसे राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील मानते हुए केन्द्र की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से अनुशंषा की जायेगी, साथ ही किसानों द्वारा क्रॉप कटिंग के पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किये जाएंगे, वह भी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को अग्रेषित किये जाऐंगे।

उक्त आपत्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार की जाएगी तथा जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा केवल राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

'किसानों को बिजली का कनैक्शन देने के टर्नकी प्रोजैक्ट में 1600 करोड़ रू. का घोटाला'

वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदे बदल रही है

- **विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार के इस गड़बड़ झाले की वजह से प्रोजैक्ट की लागत 2300 करोड़ रू. से बढ़कर 3900 करोड़ रू. हो जाएगी।**

जयपुर, 18 जुलाई (का.सं.)। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री की बजटीय घोषणा को पूरी करने के लिए प्रदेश के किसानों को खेती के लिए 1.04 लाख बिजली कृषि कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में 1600 करोड़ का ऐसा गड़बड़झाला किया जा रहा है जिसकी वजह से अब 2300 करोड़ का काम 3900 करोड़ रुपये में होगा और इसका भार अन्ततोगत्वा प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।

राठौड़ ने कहा कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरी करने के लिए 22 अप्रैल को 2300 करोड़ रुपये टैंडर निकाला था लेकिन चहेती कंपनी को ही टैंडर मिलना सुनिश्चित करने के लिए निविदा की शर्तों में 6 मई, 9 मई, 16 मई, 25 मई, 31 मई व 8 जून यानी कुल 6 बार मनमाने तरीके से संशोधन किया गया। इस संशोधन के कारण जॉइंट वैंचर वाली व दूसरे राज्यों की कई बड़ी कंपनियां बाहर हो गई तथा हर टैंडर में अधिकारियों की चहेती सिर्फ एक दो कंपनियां ही शामिल हो सकी जिन्होंने मनमर्जी करते हुए निविदा में 82 फीसदी ज्यादा रेट लगाई है और अधिकारी भी इन्ही कंपनियों को वर्कऑर्डर देने के लिए आमादा है।

राठौड़ ने कहा कि टर्नकी प्रोजेक्ट के जरिये सरकारी अधिकारियों ने टैंडर करने के साथ ही अपनी खास व चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदे बदलाने का खेल शुरू कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले ज्वाइंट वैंचर की दोनों कंपनियों में से किसी के पास भी 50 प्रतिशत काम करने का अनुभव की शर्त रखी गई थी, इससे करीब 50 कंपनियां स्वतः ही टैंडर से बाहर हो गईं। इसके साथ ही दोनों पार्टनर्स का इलैक्ट्रिकल लाइसेंस अनिवार्य करने व टर्नकी में मैटीरियल व मजदूर ठेकेदार द्वारा ही लाने जैसे टैंडर के नियमों में संशोधन से कई कंपनियां शामिल नहीं हो सकीं।

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 4.88 लाख से ज्यादा नए व लम्बित कृषि कनेक्शन जारी करने की बजटीय घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार कृषि कनैक्शन देने का कार्य टर्नकी प्रोजेक्ट से हो रहा है। डिस्कॉम प्रबंधन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा रेट पर वर्कऑर्डर देना चाहती है, जबकि अभी मात्र 1.04 लाख बिजली कृषि कनैक्शन्स के लिए टैंडर निकाले गये हैं और शेष 3.85 लाख कनैक्शन के लिए अभी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में यह भ्रष्टाचार यूं ही जारी रहा तो डिस्कॉम्स को 6400 करोड़ रूपयों का सीधा आर्थिक नुकसान होगा, जिसकी वसूली आम उपभोक्ताओं से टैरिफ बढ़ाकर की जाएगी।

राठौड़ ने कहा कि डिस्कॉम की ओर से विद्युत विनियामक आयोग में दायर टैरिफ पिटिशन के तहत आगामी तिमाही में फ्यूल चार्ज 75 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा आने की पूरी आशंका है जिसका सारा भार प्रदेश के 1.52 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली विभाग घोटालों का केन्द्र बन चुका है। पूर्व में भी अपने खुद के थर्मल पावर प्लांट में भ्रष्टाचार के कारण उत्पादन ठप्प होने से 17 रुपये प्रति यूनिट तक की महंगी बिजली उपभोक्ताओं को देकर जमकर चांदी कूटी गई। राठौड़ ने कहा कि कृषि कनैक्शनों के टर्नकी प्रोजेक्ट के अलावा सौर ऊर्जा के सोलर पैनल उत्पादन निर्माता कंपनी को फायदा पहुंचाने का कुकृत्य कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पुत्र सुमंत सिन्हा की सोलर पैनल निर्माता कंपनी रिन्यू पावर को कांग्रेस सरकार उपकृत करते हुए विशेष कस्टमाइज पैकेज दे रही है जिसमें 1 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर दोगुने से ज्यादा यानी करीब 2020 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जायेगी जबकि पूरे प्लांट के रोबोटिक व ऑटोमैटेड होने से 100 से भी कम लोगों को बमुश्किल रोजगार मिलेगा।

मुसलमानों के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

द्रौपदी मुर्मू की भाजपा की पसंद के प्रति धर्म निरपेक्ष दलों द्वारा प्रदर्शित की गई "समझौता-राजनीति" इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण है। ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक, उद्धव ठाकरे से हेमन्त सोरेन तक ये सभी नेता भाजपा की प्रत्याशी के समर्थन का निर्णय ले चुके हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति एवं तौर-तरीका दर्शाते हैं कि इनमें से कोई नेता या उसकी पार्टी भाजपा की बहुसंख्यक राजनीति को चुनौती देने के लिये राजी नहीं हैं।

जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा अपने चुनावी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करते हुये, मुस्लिम समुदाय को "अशरफ़ों तथा "पसमन्दाओं" में बाँट रही हैं। जैसा कि सी.एस. डी.एस. की हाल की एक रिपोर्ट बताती है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये कुछ दिन पूर्व हुये चुनावों में करीब 8 प्रतिशत पसमन्दा मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिये थे। भाजपा के दीर्घकालीन लक्ष्यों के एक हिस्से के रूप में, भाजपा के रणनीतिकार, एक सम्भावित कैचमेंट एरिया के रूप में, पसमन्दा मुस्लिमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। लेकिन, भाजपा ने मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ाव की शर्तें (टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट) साफ तौर पर निर्दिष्ट कर दी हैं।

मध्यप्रदेश में तेज रफ्तार बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिरी

बस में सवार सभी 13-14 लोगों की मौत हो गई

- **मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, मृतकों में अब तक राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ लोगों की पहचान हुई है। शेष की पहचान की प्रक्रिया जारी है।**

धार, 18 जुलाई (वार्ता)। मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले के सीमावर्ती खलघाट स्थित नर्मदा नदी के पुल की रेलिंग को तोड़कर यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई।

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बस हादसे के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि बस में करीब 13-14 लोग सवार थे और उनमें से कोई जीवित नहीं बचा।

इसके पहले डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया था कि बस हादसे में करीब 12 लोगों के निधन की खबर है और 15 लोगों को बचाया गया है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि हादसे के फौरन बाद लोग नदी से भाग रहे थे, त्रुटिवश उन्हें बचा हुआ मान लिया गया था। ताजा जानकारी के अनुसार बस में 13 से 14 लोग सवार थे। उनमें से कोई जीवित नहीं बचा।

उन्होंने बताया कि मृतकों में अब तक राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ लोगों की पहचान हुई है। शेष की पहचान की प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्री ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल को बचाने के फेर में बस नीचे जा गिरी।

तलाक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तलाक़-ए-हसन तथा अन्य सभी तरह की इकतरफा एक्स्ट्रा-जुडिशियल तलाक़ों को असंवैधानिक घोषित किया जाये तथा केन्द्र को निर्देश दिये जायें कि केन्द्र तलाक़ के लिये सभी धर्मों एवं स्त्री-पुरुष दोनों के लिये समान प्रकार के आधार रखने के लिये गाइडलाइन तैयार करे।

याचिका में कहा गया है कि तलाक़ों का "न तो मानवाधिकारों तथा आम बराबरी के आधुनिक सिद्धांतों के साथ ताल-मेल या सुसंगति है और न ये इस्लामिक राष्ट्रों के व्यवहार का अभिन्न एवं अनिवार्य हिस्सा ही हैं क्योंकि कई इस्लामिक देश ऐसी प्रथाओं को पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं।

दिसंबर 2020 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ शादी करने वाली, वादी मुस्लिम पत्रकार का कहना है कि वह इकतरफा तलाक़-ए-हसन की शिकार है क्योंकि उसके माता-पिता को दहेज देने के लिये मजबूर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी, उसे उसके पति तथा पति के परिवारजनों ने बड़ा दहेज़ न मिलने के कारण यातनाएं दीं।

उसकी वकील ने कहा कि उसके पिता द्वारा आगे और दहेज देने से इनकार कर दिये जाने पर, उसके पति ने एक वकील के माध्यम से उसे तलाक़ -ए-हसन दे दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 और 25 के पूरी तरह विरुद्ध है। याचिका में यह मांग भी की गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 तथा डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, 1939 को शून्य तथा असंवैधानिक घोषित किया जाये।

बी.टी.पी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष को इन्वॉल्व करती । उससे बातचीत करती और राष्ट्रपति जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने लाने की कोशिश करती । वो बेहतर होता, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार के चुनाव छोड़कर 15 बार लगातार हमेशा कोई न कोई उम्मीदवार सामने आए हैं।

यह ज्यादा बहस का विषय नहीं होना चाहिए। इसे विचारधारा की लड़ाई के संदर्भ में लेना चाहिए।"

हिमालय की सैन्ट्रल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन्टेन्सिटी" पिछले दो दशकों में करीब 10 प्रतिशत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की विसंगति और बढ़ी है।

जहाँ पूर्ववर्ती अध्ययनों के वर्षों से, इस विसंगति को पैदा करने एवं बनाये रखने में तापमान की भूमिका को महत्व दिया जाता रहा है, वहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि, असामान्य स्थिति के कारक के रूप में, प्रैसिपिटेशन (वर्षा या बर्फबारी) के असर पर जोर दिया गया है। शोधकर्ताओं ने भी असामान्य स्थिति के कारक के रूप में वर्षा के प्रभाव पर ही जोर दिया है।

वैज्ञानिकों की गणनाएं बताती हैं कि काराकोरम के मूल ग्लेशियर क्षेत्रों में बर्फबारी की मात्रा के मामले में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गैर-(डब्ल्यू.डी) स्रोतों से प्राप्त वर्षा में 17 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। इस तथ्य से भी शोधकर्ताओं के दावों को और भी बल मिला है।

डॉ. कुमार ने कहा, "इस विसंगति से भविष्य में विलम्ब होने की दिशा में आशा की एक बहुत ही मंद सही, लेकिन किरण तो दिखाई दी है। विसंगति को नियंत्रित करने में (डब्ल्यू.डी.) के महत्व को पहचान लेने के बाद, इनके आगामी व्यवहार से हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों का भविष्य जरूर तय होने की संभावना है।"

केरल में मंकीपॉक्स का एक और मामला

तिरुवनंतपुरम, 18 जुलाई (वार्ता)। केरल में सोमवार को भारत में मंकीपॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी दी। जार्ज ने बताय कि 13 जुलाई को दुबई से कन्नूर पहुंचे एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने मंकीपॉक्स का परीक्षण कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें कन्नूर के सरकारी मैडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके संपर्क में आने वालों की निगरानी की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले 14 जुलाई को केरल में भारत के पहले मंकीपॉक्स मामले की पुष्टि हुई थी, जब संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) से आए एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने तिरुवनंतपुरम के मैडिकल कॉलेज अस्पताल में सकारात्मक परीक्षण किया था।

जी.एस.टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाएगा। इसके अलावा खुदरा व्यवसायी जी.एस.टी. से बच सकता है अगर वह पैक में वस्तु खरीदता है और उसे फुटकर में बेचता है क्योंकि ऐसी सप्लाई जी.एस.टी. शुल्क के दायरे में नहीं आएगी। हालांकि यह पैकेज़्ड आइटम्स की बिक्री को प्रोत्साहित करने की सरकार की घोषित नीति के विरूद्ध है क्योंकि लूज़ में बेचने पर इससे मिलावट को बढ़ावा मिलेगा। तथापि, जी.एस.टी. उस पैकेज पर लागू होगा जिसमें कई रिटेल पैक शामिल हों, जैसे कि 10 किलो आटे के 10 रिटेल पैक का एक पैकेज। तो फिर जी.एस.टी. 10 कि.ग्रा. पैक की खुदरा बिक्री पर लागू होगा क्योंकि अन्ततः बिक्री एक खुदरा उपभोक्ता को की जाएगी।

संसद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैंकेया नायडू ने भी इसी प्रकार दोपहर से पहले सदन स्थगित कर दिया था।

इससे पूर्व दोनों सदनों में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके अलावा, दोनों सदनों के पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक-संवेदना को प्रस्ताव भी पारित किया गया।

राष्ट्रपति चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, 99 प्रतिशत मतदान हुआ

गुजरात से लेकर यू.पी तक एन.सी.पी., कांग्रेस और सपा में बड़ी फूट देखने को मिली

- **एनडीए ने अपना कुनबा इस चुनाव में और मजबूत करके दिखाया।**
- **गुजरात में छोटूभाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी मुर्मू को समर्थन दिया।**
- **मुलायम सिंह यादव व लालू यादव जैसे कई दिग्गज वोट नहीं कर सके।**

नई दिल्ली, 18 जुलाई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में मतदान जारी है। एन.डी.ए. ने एक तरफ अपना कुनबा इस चुनाव में मजबूत करके दिखाया है तो वहीं विपक्षी खेमे को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा है। गुजरात से लेकर यू.पी. तक में एन.सी.पी., कांग्रेस और सपा में फूट देखने को मिली है। गुजरात में एन.सी.पी. के विधायक कांधल एस. जडेजा ने पार्टी के रुख से अलग एन.डी.ए. की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया।

उन्हें लेकर पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि वह पार्टी से अलग रुख अपना सकते हैं। एन.सी.पी. ने यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया था। इसके अलावा झारखंड से एन.सी.पी. विधायक कमलेश सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाल दिया। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता छोटूभाई वसावा ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी नेता को वोट दिया है, जिसने गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रपति चुनाव में फूट का सामना करना पड़ा है। एक तरफ अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने खुलेआम द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है तो वहीं सपा के अपने ही विधायक शहजील इस्लाम ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बरेली के भोजीपुरा से पार्टी विधायक शहजील इस्लाम बीते कुछ वक्त से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे।

शिवपाल यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वह ऐसे शख्स को वोट नहीं करेंगे, जिसने एक दौर में मुलायम सिंह यादव को आई.एस.आई. एजेंट करार दिया था। कांग्रेस भी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने में फेल रही है। ओडिशा से पार्टी के विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी एन.डी.ए. की राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट दिया है।

क्या नई शिवसेना खड़ी करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे?

बालासाहेब के समय के वरिष्ठ नेता रामदास कदम और आनंदराव अदसुल को पार्टी से बाहर निकाला

- **दरअसल में, रामदास कदम ने ठाकरे के एक्शन से पहले ही पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर मातोश्री (ठाकरे आवास) पर भेज दिया था, लगता है कि, उनका इस्तीफा देखने के बाद ठाकरे ने रामदास कदम को बाहर निकालने का फैसला लिया।**

मुंबई, 18 जुलाई। महाराष्ट्र में अपने विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे फूंक-फूंककर कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में वह बचे-खुचे पदाधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं। इसके तहत उद्धव ने दो वरिष्ठ शिवसेना नेताओं के खिलाफ अहम कदम उठाया है। फैसले के तहत उद्धव ने रामदास कदम और आनंदराव अदसुल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन दोनों नेताओं के ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इससे पूर्व दिन में खबर आई थी कि रामदास कदम ने अपना इस्तीफा मातोश्री पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि रामदास के बेटे योगेश कदम पहले ही शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं।

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना के अस्तित्व को बचाने का सवाल उठने लगा है। इसी के तहत उद्धव पार्टी की ओवरहॉलिंग करने में जुटे हुए हैं। उनके सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बी.एम.सी. के चुनाव हैं। इसके बाद 2024 में होने वाले आम चुनावों पर भी उद्धव की नजर होगी। बता दें कि सोमवार को ही उद्धव ने महाराष्ट्र के कई जिलों में 100 से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। उद्धव ने मुंबई, पालघर, यवतमाल, अमरावती समेत कई अन्य जिलों में 100 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्सः01562-256908